

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

पोषण की दृष्टि से सुरक्षित भारत के लिए
दूध की कमी को दूर करना

www.nextias.com

पोषण की दृष्टि से सुरक्षित भारत के लिए दूध की कमी को दूर करना

संदर्भ

- लंबे समय से भारत वर्गीज कुरियन द्वारा प्रारंभ की गई श्वेत क्रांति की आपूर्ति पक्ष की अविश्वसनीय सफलता का उत्सव मनाता रहा है। हालाँकि, अब मांग पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दूध सबसे कमजोर जनसंख्या तक पहुँचे।

श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ्लड) का परिचय

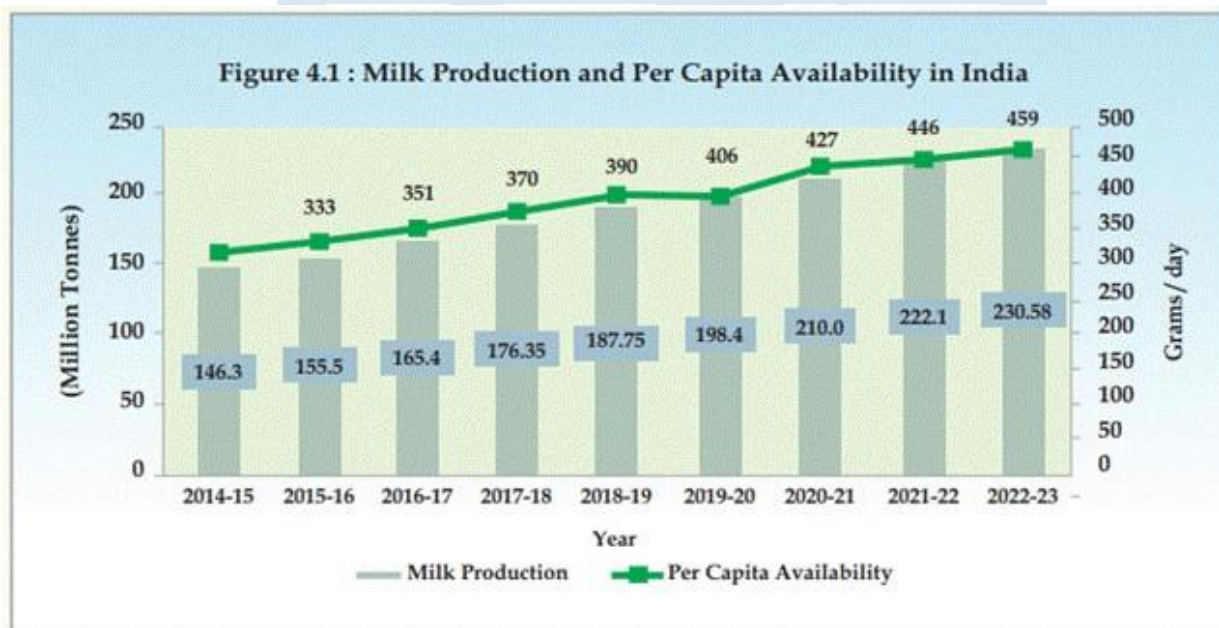
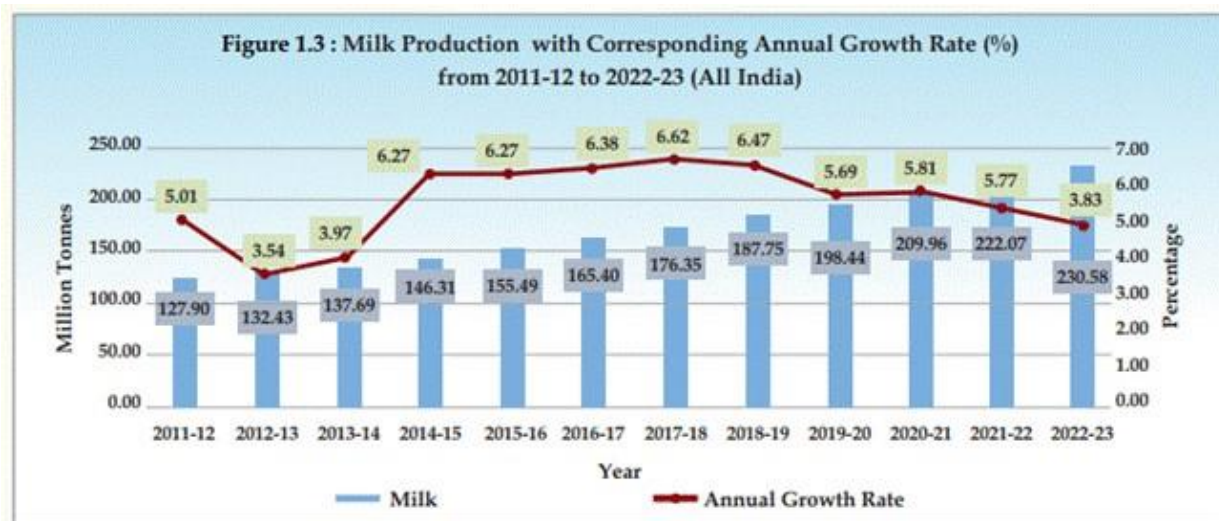
- यह 1970 में भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा प्रारंभ किया गया एक परिवर्तनकारी डेयरी विकास कार्यक्रम था।
- इसका उद्देश्य एक राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाना था, जो भारत भर के उत्पादकों को 700 से अधिक कस्बों और शहरों में उपभोक्ताओं से जोड़ता था।
- इस प्रयास से न केवल दूध का उत्पादन बढ़ा, बल्कि मध्यस्थों को समाप्त करके उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित मूल्य भी सुनिश्चित हुआ।

ऑपरेशन फ्लड के चरण:

- चरण I (1970-1980):** विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा दान किए गए स्किमड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल की बिक्री से वित्तपोषित, इस चरण ने 18 प्रमुख दूध शेडों को प्रमुख महानगरीय शहरों से जोड़ा, जिससे डेयरी नेटवर्क के लिए एक मजबूत आधार स्थापित हुआ।
- चरण II (1981-1985):** दूध शेडों की संख्या 18 से बढ़ाकर 136 कर दी गई और शहरी बाजारों को बढ़ाकर 290 कर दिया गया।
 - इस चरण के अंत तक, 4.25 मिलियन दूध उत्पादकों के साथ 43,000 ग्राम सहकारी समितियों वाली एक आत्मनिर्भर प्रणाली स्थापित की गई।
- चरण III (1985-1996):** डेयरी सहकारी आंदोलन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, वर्तमान नेटवर्क में 30,000 नई सहकारी समितियों को जोड़ा गया।
 - पशु स्वास्थ्य और पोषण में अनुसंधान और विकास पर बल दिया गया, जिससे दूध की उत्पादकता में वृद्धि हुई।

मुख्य परिणाम

- विश्व स्तर पर भारत 230.58 मिलियन टन प्रति वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23, 3.83% की वार्षिक वृद्धि) के साथ दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और यह विश्व दूध उत्पादन का 25% है, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है।
 - 2022-23 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 459 ग्राम/दिन है।
 - शीर्ष दूध उत्पादक राज्य:** राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश सामूहिक रूप से भारत के कुल दूध उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा हैं।
- पशुधन जनसंख्या:** देश में 303.76 मिलियन गोजातीय और 74.26 मिलियन बकरियों सहित एक विशाल पशुधन जनसंख्या है, जो इसके डेयरी क्षेत्र की व्यापक नींव को रेखांकित करती है।



पोषण में दूध क्यों महत्वपूर्ण है?

- दूध को प्रायः 'संपूर्ण भोजन' कहा जाता है क्योंकि इसमें वृद्धि, विकास और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं।
 - **हड्डियों का स्वास्थ्य:** कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर दूध बच्चों में ऑस्टियोपोरोसिस और विकास में रुकावट को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
 - **संज्ञानात्मक विकास:** दूध में उपस्थित ओमेगा-3 फैटी एसिड और अन्य पोषक तत्व बच्चों में मस्तिष्क के कार्य एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं में सहायता करते हैं।
 - **प्रतिरक्षा बूस्टर:** विटामिन A, B12 और जिंक की मौजूदगी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाती है, जिससे रोग की संवेदनशीलता कम होती है।
 - **प्रोटीन स्रोत:** यह उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करता है जो मांसपेशियों के विकास और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है।

- शोध से ज्ञात हुआ है कि दूध की खपत छह महीने से पाँच वर्ष की उम्र के भारतीय बच्चों में बौनेपन, कम वजन और मानवजनित विफलता की कम संभावनाओं से जुड़ी है।
 - हालाँकि, महत्वपूर्ण भोजन के रूप में दूध की पहुँच विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक-आर्थिक समूहों और जनसांख्यिकी में असमान बनी हुई है।

प्रमुख चिंताएँ एवं चुनौतियाँ

- **खपत में असमानता:** NSSO द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (HCES) के अनुसार:
 - उच्च आय वाले दशमलव में परिवार निम्न आय वाले दशमलव की तुलना में प्रति व्यक्ति तीन से चार गुना अधिक दूध का उपभोग करते हैं।
 - भारत के सबसे गरीब 30% परिवार भारत के दूध का केवल 18% उपभोग करते हैं।
 - शहरी परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित अधिकांश दूध के बावजूद ग्रामीण परिवारों की तुलना में प्रति व्यक्ति लगभग 30% अधिक दूध का उपभोग करते हैं।
- **समान दूध पहुँच में बाधाएँ:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आँकड़ों के अनुसार, समृद्ध परिवारों की तुलना में गरीब परिवारों में दूध की खपत अत्यधिक कम है।
 - ग्रामीण क्षेत्र, विशेष रूप से बिहार, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे डेयरी-समृद्ध राज्यों की तुलना में कम सेवन स्तर की रिपोर्ट है।
- **आय असमानताएँ और वहनीयता:** गरीब परिवार नियमित रूप से दूध नहीं खरीद सकते, जिससे यह मुख्य वस्तु के बजाय विलासिता बन जाती है।
 - डेयरी मुद्रास्फीति ने दूध को महँगा बना दिया है, हाल के वर्षों में कीमतों में वार्षिक 12-15% की वृद्धि हुई है।
- **क्षेत्रीय उत्पादन असमानताएँ:** पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में दूध का उत्पादन अत्यधिक केंद्रित है, जबकि अन्य राज्यों में आपूर्ति की कमी है।
 - दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की चुनौतियाँ ताजे दूध की उपलब्धता को सीमित करती हैं।
- **सांस्कृतिक और आहार संबंधी कारक:** भारत के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, दूध आहार का पारंपरिक हिस्सा नहीं है, जिससे खपत कम होती है।
 - धार्मिक और नैतिक चिंताएँ कुछ समुदायों के बीच डेयरी सेवन को प्रभावित करती हैं।
- **अपर्याप्त कोल्ड चेन और आपूर्ति रसद:** ग्रामीण क्षेत्रों में उचित प्रशीतन और भंडारण सुविधाओं की कमी से दूध खराब होता है और बर्बाद होता है।
 - असंगत आपूर्ति शृंखलाएँ अविकसित क्षेत्रों में दूध के वितरण को सीमित करती हैं।

दूध की कमी को समाप्त करना: समाधान और रणनीतियाँ

- **कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में डेयरी के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना:** सहकारी डेयरी खेती को प्रोत्साहित करने से पिछड़े राज्यों में दूध उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।
 - कोल्ड स्टोरेज एवं परिवहन में निवेश से दूध वितरण में सुधार होगा और दूध खराब होने की संभावना कम होगी।
- **कम आय वाले परिवारों के लिए सब्सिडी वाले दूध कार्यक्रम:** सरकार दूध को फोर्टिफाईड और राशन-आधारित योजनाएँ प्रारंभ कर सकती है, जिससे वंचित परिवारों के लिए सस्ती दूध तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

- स्कूल भोजन कार्यक्रमों में बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए दूध को शामिल किया जाना चाहिए।
- **वैकल्पिक डेयरी उत्पादों को प्रोत्साहित करना:** फोर्टिफाइड दूध पाउडर और डेयरी-आधारित पोषण संबंधी पूरक जैसे कम लागत वाले डेयरी विकल्पों की उपलब्धता का विस्तार करें।
 - कम दूध की खपत वाले क्षेत्रों में स्थानीय रूप से उपलब्ध डेयरी विकल्पों को बढ़ावा देना।
- **पोषण शिक्षा के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना:** आहार में दूध के महत्व पर जागरूकता अभियान कम खपत वाले क्षेत्रों को लक्षित करना चाहिए।
 - स्कूल और सामुदायिक केंद्र माता-पिता एवं बच्चों को डेयरी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- **छोटे और सीमांत डेयरी किसानों का समर्थन करना:** वित्तीय प्रोत्साहन, पशु चिकित्सा सहायता और बेहतर बाजार संपर्क प्रदान करके छोटे पैमाने के डेयरी किसानों को सशक्त बनाया जा सकता है।
 - सतत डेयरी फार्मिंग प्रथाओं को प्रोत्साहित करने से दूध की उत्पादकता बढ़ेगी और साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।

डेयरी विकास को समर्थन देने वाली प्रमुख सरकारी पहल

- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (POSHAN) और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) जैसे कार्यक्रमों का लाभ दूध या दूध से बने उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए उठाया जा सकता है।
- सामाजिक-सांस्कृतिक प्राथमिकताओं और सहनशीलता के साथ संरेखित दूध या दूध से बने उत्पादों को एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करना भी महत्वपूर्ण है।
- अन्य प्रमुख पहल हैं:
 - राष्ट्रीय डेयरी योजना (NDP);
 - डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF);
 - राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM);
 - राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD);
 - पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट (A-HELP);
 - डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आदि।

निष्कर्ष

- जैसे-जैसे भारत 2025-26 के केंद्रीय बजट के करीब पहुँच रहा है, सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए इन असमानताओं को दूर करना आवश्यक है।
- दूध तक समान पहुँच सुनिश्चित करना पोषण की दृष्टि से सुरक्षित भारत में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जिससे लाखों कमजोर व्यक्तियों को लाभ होगा और समग्र कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।

Source: TH



दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. भारत अपनी सबसे सुभेद्य जनसंख्या के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूध की कमी को कैसे प्रभावी ढंग से समाप्त कर सकता है, और इस प्रयास में सरकारी नीतियों और सामुदायिक पहलों की क्या भूमिका होनी चाहिए?